घोटालेबाज सरकार का सुप्रीम कोर्ट क्या बिगाड़ लेगी

मनोज कुमार झा

ऐसे तो यह सभी को पता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच एजेंसी होने का दावा करने वाली सीबीआई कतई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं है। अगर यह स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वायत्त होती तो उच्च पदासीन कई नौकरशाह और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कई मंत्री सलाखों के पिछे होते।

हमें सीबीआई निदेशक रंजित सिन्हा के प्रति आभारी होना चाहिये कि उन्होंने, मज़बूरी में ही सही, सीबीआई की वास्तविक हैसियत का सार्वजनिक खुलासा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में सीबीआई को पिंजरे में कैद वह तोता बताया जो मालिक जैसा कहे, वही बोलता है। कोयला घोटाले की जांच रपट में कानून मंत्री और कोयला मंत्रालय के आला अफ़सरों ने मनचाहा बदलाव करवाया। इस तरह स्वायत्त एजेंसी कही जाने वाली सीबीआई के साथ सरकार ने बलात्कार किया। ऐसा सरकार लगातार करती रही है। सिर्फ मनमोहन-सोनिया सरकार नहीं, तमाम पूर्ववर्ती सरकारें भी।

आजतक शायद ही ऐसा कोई बड़ा मामला हो, जिसमें सीबीआई की जांच किसी अंजाम तक पहुंची हो और किसी रसूखदार नेता को सज़ा मिली हो। सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ यूपीए सरकार नहीं, तमाम सरकारें राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिये करती रही हैं। इस सरकार ने यदि सीबीआई का इस्तेमाल मुलायम, मायावती और करूणानिधि के बेटों के खिलाफ़ किया है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है ऐसा करके सरकार ने 'राजधर्म' का पालन किया है। सीबीआई

मनमोहन : ईमानदार छवि के करिश्माई घोटाले

के डंडे से सरकार न केवल अपने विरोधियों को बल्कि अपने समर्थकों को भी डराये रखने का काम करती है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार सीबीआई को स्वतंत्र करने के लिये कोई कानून बनाये, नहीं तो वह इस बारे में खुद कोई फ़ैसला करेगी। यह भी एक अजीब ही टिप्पणी है। सीबीआई तो 'स्वायत्त,स्वतंत्र, निष्पक्ष' जांच एजेंसी है ही, फिर कानून की जरूरत क्यों? यह सीबीआई की मजबूरी है कि उसे सरकार के इशारे पर काम करना पड़ता है और क्या सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं? सुप्रीम कोर्ट इस सरकार का या किसी भी सरकार का क्या बिगाड़ लेगी? वह सिर्फ फैसला दे सकती है। सरकार फैसले को माने, न माने, उसकी मर्जी? कोई भी अदालत अगर किसी आम आदमी के खिलाफ़ सजा सुनाती है, तो सरकारी अमला उस पर तुरंत अमल करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बताए कि उसने कितने राजनेताओ, नौकरशाहों के खिलाफ़ सज़ा सुनाई हो, जिस पर तुरंत अमल हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट इस बात को न भूले कि उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं। उसके फैसले पर अमल नहीं होता तो वह नोटिस आदि जारी करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो अच्छा किया सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने जो सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि वे सरकार के अंग हैं और मंत्रियों-नौकरशाहों को जांच रिपोर्ट दिखाना व उनके कहे अनुसार जांच रिपोर्ट में फेर-बदल करना उनकी मजबूरी है। उन्होंने मूल रिपोर्ट और कानून मंत्री अश्वनी कुमार एवं कोयला मंत्रालय के आला अफसरों के कहे अनुसार फेरबदल की गई रिपोर्ट, दोनों अदालत के सामने रख दी। इससे जनता को पता चल गया कि सीबीआई की कार्य-प्रणाली क्या है और कैसे कदम-कदम पर सरकार से दिशा-निर्देश हासिल करती है।

कोयला घोटाले में स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फंसे हुए हैं। वैसे तो यूपीए सरकार ने एक से बढ़कर एक जितने घोटाले किए, सरकार के मुखिया होने के कारण मनमोहन सिंह उसके लिये जिम्मेदार होते हैं। और यूपीए की चेयर पर्सन होने के नाते सोनिया भी इन घोटालों के लिये जरा भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन पूरे देश ने यह देखा कि बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी क्वात्रोची की उन्होंने किस तरह मदद की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लंदन स्थित उसके खातों को सील किए जाने का आदेश दिए जाने के बाद सोनिया की मदद से ही वह खातों से पैसे निकाल कर भाग निकला। क्वात्रोची से उनके पारिवारिक और मित्रतापूर्ण संबंधों को कौन नहीं जानता। सोनिया के दामाद राबर्ट बढेरा ने अपने ताबेदार भुपेन्द्र सिंह हुड्डा के सहयोग से हरियाणा में जमकर भूमि घोटाले किए हैं। उनका हाथ पकड़ने वाला कौन है? उसे किसी कोर्ट की परवाह नहीं। यूपीए सरकार लुटेरों का गिरोह है। जिस निर्ममता से यह देश की गरीब जनता को लगातार लूटने में लगा हुआ है, उससे यह साबित हो गया है कि अब जनतंत्र ने अपने चेहरे पर से नकाब नोच लिया है। इसके पैने दांत और खून सनी लपलपाती जीभ सबको दिखाई दे रही है।

दरअसल यह जनतंत्र नहीं है, यह नौकरशाही तंत्र नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं, ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है। एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में सबसे बड़ा नौकरशाह प्राइममिनिस्टर होता है। अदालतें तो महज़ दिखावा हैं और जांच-एजेंसियां भी।

अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार से कौन अवगत नहीं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार । फिर सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगा सकती है। भ्रष्टाचार के बिना नौकरशाह तंत्र फल-फूल नहीं सकता। बेशुमार टैक्सों से इस सरकार का पेट नहीं भरता। इसके लिए जरूरी है जन संसाधनों-प्राकृतिक संसाधनों की लूट। कोयले की लूट, तेल की लूट, बहुमूल्य खनिज पदार्थों की लूट-टाटाओं, अंबानियों, बिड़लाओं के लिए, विदेशी महाकाय निगमों के लिये लगातार लूट। इसी लूट के धन का जो कमीशन मिलता है, उसी पर मंत्री से लेकर संतरी तक अपना ठाठ-बाट बनाता है।

सुप्रीम कोर्ट को समझ लेना चाहिये कि उसके हाय-तौबा मचाने से इस नौकरशाह तंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 'स्वायत्त' सीबीआई इस लूटतंत्र का अंग है, वैसे ही अदालतें भी। और जनता, जिसके नाम पर यह 'जनतंत्र' चल रहा है, वह महज वोट देने की मशीन बन कर रह गई है। नेताओं के लिये जनता का महत्व सिर्फ इतना ही है कि वह उन्हें वोट दे और इसके बाद जाये जहन्नुम में, उन्हें कोई परवाह नहीं।

कर्नाटक : आखिरकार येदियुरप्पा ही जीते!

अब चुनाव में भ्रष्टाचार ही जीतेगा

कर्नाटक में भाजपा की हार तय थी। यह भी स्पष्ट हो चुका था कि जीत कांग्रेस की होगी। इसकी वजह ये है कि तीसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। लेकिन इस हार से न भाजपा को निराश होने की जरूरत है और न ही इस जीत से कांग्रेस को अति उत्साह में आना चाहिए। इस वर्ष 6 राज्यों में चुनाव हैं। इन चुनावों से बहुत कुछ स्पष्ट होगा। वैसे, इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि राज्य विधान सभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे ही हावी रहते हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस अपनी जीत को 'पप्पू पास हो गया' के रूप में देख रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2014 में राहुल बाबा 'करिश्माई' साबित होगे। यह कांग्रेस की ग़लतफ़हमी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में न तो पप्पू (राहूल गांधी) पास हुआ और न ही फेकू (नरेन्द्र मोदी)फेल हुआ, बल्कि वोटकटवा (येदिरप्पा)ने अपना कमाल दिखाया और बीजेपी को ले डूबा-'हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे।' यदि येदियुरप्पा बीजेपी से अलग न होते तो कर्नाटक में कांग्रेस कभी भी न जीत पाती। इसलिए उसे अपने 'पप्पू' पर ज़्यादा नाज नहीं करना चाहिये। अगर पप्पू पास होता तो यूपी में अखिलेश की सरकार नहीं बनती।

दरअसल, कर्नाटक में हारने के बाद भी जीत येदियुरप्पा की हुई है। जीत भ्रष्टाचार की हुई है। जाहिर है, जन की भूमिका इस जनतंत्र (लूटतंत्र) में अत्यंत सीमित है। येदियुरप्पा ने भाजपा नेतृत्व को दिखा दिया कि महाभ्रष्ट होने के बावजूद उनकी हैसियत क्या है। कर्नाटक में भाजपा

येदियुरप्पा : मुझे नहीं खाने दोगे तो तुम भी कैसे खा लोगे?

के आधार को येदियुरप्पा ने ही खड़ा किया था, पर जब उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार सभी हदों को पार करने लगा तो पार्टी आलाकमान को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। जिस वक्त येदियुरप्पा और उनके सहयोगियों का भ्रष्टाचार मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ था, तभी लालकृष्ण आडवाणी ने भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा शुरू की थी, इसलिये उनकी खुब किरकिरी हुई। आडवाणी एक साम्प्रदायिक नेता हैं, पर भ्रष्ट नहीं। वैसे, बीजेपी में भ्रष्ट नेताओं की कोई कमी नहीं है, पर भ्रष्टाचार उजागर होने पर उन्हें पद छोड़ना पड़ता है, जैसे गडकरी को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। बीजेपी में भ्रष्ट नेताओं को दिखावे के लिये ही सही, किनारे लगाने की परिपाटी हैं, पर कांग्रेस में नहीं। यहां बड़े-बड़े 'भ्रष्टासुर' बेखौफ पार्टी एवं सरकार में अहम पदों पर ठसक के साथ बने रहते हैं। महाभ्रष्ट और सांप्रदायिक यह है आजाद भारत पर सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस का चरित्र। बीजेपी तो हिंदू सांप्रदायिकता की ही सवारी गांठती है, पर कांग्रेस तो जब जैसा मौका मिला, हिंदू-मुस्लिम, दोनों सांप्रदायिकता की सवारी गांठने से बाज नहीं आती। बहरहाल, कर्नाटक में जीत के साथ ही, कांग्रेसी पप्पू की शान में कसीदे पढ़ने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कांग्रेस उपाध्यक्ष पप्पू उर्फ राहुल गांधी आने वाले चुनावों में टिकटार्थियों की आशाओं के मुख्य केंद्र बने हुए हैं। पप्पू कांग्रेसी नेताओं की क्लास लगा रहे हैं। नया वर्क-कल्चर लाने की कोशिश में हैं, पर चमचागीरी किसे नहीं भाती। पप्पू के आगे-पीछे चमचों की अच्छी खासी फौज खड़ी हो चुकी है। कभी-कभी पप्पू गुरू गंभीर दार्शनिक मुद्रा में आ जाते हैं, उस वक्त जनता के रक्त पर पल रहे इस परजीवी के मुख से निकली बातें हास्यास्पद होने के साथ-साथ क्रोध भरकाने वाली होती हैं।

कर्नाटक से बीजेपी को भी सबक लेने की जरूरत है। लगभग 2000 लोगों की नृशंस हत्या के लिये प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेवार नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किये जाने पर आत्मघाती साबित हो सकते हैं। गुजरात छोड़ अन्य राज्यों में अपने प्रभाव की हकीकत से वो वाकिफ़ हैं, यही कारण है कि बहुत मुश्किल से कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिये राजी हुए और कम से कम चुनाव प्रचार किया। उत्तर भारतीय राज्यों में तो वो और भी ज्यादा अलोकप्रिय हैं। यूपी, बिहार, बंगाल जैसों राज्यों में अगर वो चुनाव प्रचार करने गए तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुतेरे भाजपा समर्थक वोटर चाहते हैं कि मोदी को छोड़ पार्टी किसी और को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करे।

गुजरात के विकास मॉडल की हकीकत लोगों को समझ में आने लगी है। गुजरात वो विकसित राज्य है, जहां औरतें 30-30 हजार रुपये में बिकने को मजबूर हैं और सूरत जैसे विकसित नगर में अंधेरा घिरते ही खुलेआम सड़क किनारे ही देह-व्यापार शुरू हो जाता है। विदेशी ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करने वाले कॉरपोरेट दिग्गजों के प्रिय मोदी इन बातों से नावाकिफ़ हों, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो इन बातों को कोई महत्त्व नहीं देते। कॉरपोरेट को एक हिटलर की जरूरत है। मोदी में उन्हें वो हिटलर दिखाई पड़ रहा है। पर मोदी के लिये प्रधानमंत्री बनने की राह इतनी आसान नहीं। न ही पप्पू के लिये। लेकिन दोनों में एक बात समान है। मोदी अगर बीजेपी को डुबोएंगे तो पप्पू कांग्रेस को। खास बात यह है कि ये पप्पू कांग्रेसी मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोलता, जिन्होंने घोटालों का वर्ल्ड रिकार्ड कायम किया है। इसकी वजह है कि ये पप्पू भ्रष्टाचार की कोख से ही पैदा हुआ है।

भ्रष्टाचार इस देश की राजनीति में कुछ इस कदर रच-बस गया है कि अब चुनावों में भी भ्रष्टाचार ही जीतेगा, जैसे येदियुरप्पा। इसलिए, जनता को चुनावों से अलग कोई दूसरा विकल्प तलाशना चाहीए, क्योंकि तय है चुनावों में भ्रष्टाचार ही जीतेगा।

-मनोज कुमार झा